

**विधि एवं न्याय मंत्रालय**

मांग संख्या 62

निर्वाचन आयोग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट, 2004-2005			संशोधित, 2004-2005			बजट, 2005-2006			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	...	11.50	11.50	...	11.50	11.50	...	11.85	11.85	
पूंजी	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
<b>जोड़</b>	...	<b>11.50</b>	<b>11.50</b>	...	<b>11.50</b>	<b>11.50</b>	...	<b>11.85</b>	<b>11.85</b>	
<b>निर्वाचन</b>										
1. भारत का निर्वाचन आयोग	2015	...	11.50	11.50	...	11.50	11.50	...	11.85	11.85
<b>कुल जोड़</b>		...	<b>11.50</b>	<b>11.50</b>	...	<b>11.50</b>	<b>11.50</b>	...	<b>11.85</b>	<b>11.85</b>

(करोड़ रुपए)

यह प्रावधान मुख्यतः भारत के निर्वाचन आयोग तथा सीमा निर्धारण आयोग के स्थापना संबंधी व्यय के लिए है। इसमें आयोग की वैबसाइट के अनुरक्षण तथा राष्ट्रीय मतदाता जागरुकता अभियान की योजना के लिए प्रावधान भी शामिल है।